

श्री. जिला कलेक्टर (पुणे)  
श्री. जिला कलेक्टर (पुणे)

अपने जीवनकाल में ही उक्त श्री अपीलाटस व रेस्पॉन्डेंट्स सं 1 व 2 के नाम से इतकाल दर्ज नहीं हो सका क्योंकि विवाहित श्री दयालसिंह व भगवानकौर ने दयालसिंह व भगवानकौर की मृत्यु पूर्व में ही चुकी थी तो मृतक व्यक्तियों के नाम इतकाल मृतक दयालसिंह जिसकी मृत्यु दिनांक 15-2-94 को हो गई थी। अपीनास्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से दिनांक 23-11-12 को अपीलाधीन अपीलाटस व रेस्पॉन्डेंट्स सं 1 व 2 के नाम से दर्ज राजस्व रेकार्ड में थी। बड़ा पटवार हल्का मटीलीरातान मुं 0 नं 5 के किला नं 1 ता 25 की नहरी श्री प्ररुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि एक 14 एक की गई है।

अन्तर्गत तहसीलदार, सादुलशहर के आदेश दिनांक 30-11-12 के विरुद्ध प्ररुत अपीलाट द्वारा प्ररुत अपील श्री राजस्व अधिनियम की धारा 75 के

दिनांक : 31-12-15

आदेश

1. श्री जयलसिंह टुंरना, अधिवक्ता, अपीलाटस
2. श्री हंसराज तनेजा, अधिवक्ता, रेस्पॉन्डेंट्स सं 1 व 2
3. श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पॉन्डेंट्स सं 03

उपरिष्ठत :

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार श्रीगंगानगर इतकाल सं 0 345 दिनांक 23.11.12

रेस्पॉन्डेंट्स

1. करलारसिंह पुत्र दयालसिंह जाति मजहबी सिख निवासी 14 एक बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. गोपालसिंह पुत्र दयालसिंह जाति मजहबी सिख निवासी 14 एक बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जारिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर।

बनाम

अपीलाधीन

1. जयलसिंह
2. दर्शनसिंह पिसरन दयालसिंह जाति मजहबी सिख निवासी 14 एक बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. महेंद्रकौर पुत्री दयालसिंह पत्नी करनलसिंह निवासी मसानी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. बलविन्दकौर पुत्री दयालसिंह पत्नी अर्जनासिंह निवासी मोनेवाला हैड तहसील धरसाना जिला श्रीगंगानगर।
5. करलारकौर पुत्री दयालसिंह पत्नी कर्मासिंह जाति मजहबी सिख निवासी सफीपुरा तहसील जमरावा जिला लुधियाना (पंजाब)

अपील इतकाल प्रकरण सं 0 42 / 13

पुणे जिला अधिकाः : कणासह गाठवाल, आर००२०२५०



ऑलिंपिक कमेटी (भारत)  
ऑलिंपिक कमेटी (भारत)

स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गए मूल डेटाकाल  
2590 दिनांक 19-2-87 के आधार पर खोला जाकर दिनांक 23-11-12 को  
पत्रावली के अवलोकन से पया गया कि अधीनस्थ डेटाकाल सनद सं0  
कराने हेतु चुनौति दी गई है।

23-11-12 को स्वीकृत किया गया है, को हस्तगत अधील के माध्यम से निरस्त  
कमांक 2590 दिनांक 19-2-87 को जारी हुई है, के आधार पर दिनांक  
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ डेटाकाल सं0 345 जो खातेदारी सनद  
बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पारित किया जा सकता है। अतः अधील खारिज की जावे।  
दृष्टान्त पेश कर निवेदन किया है कि मूलक व्यक्ति के हक में कोई भी आदेश  
गया है। अपने पक्ष के समर्थन में ए आई आर 1981 (राज0) पृज 89 का न्यायिक  
है। उस वक्त गिरखातेदारी मसि थी। मूलक के विरुद्ध आदेश पारित नहीं किया  
हिस से पर काबिज है। माता पिता ने अपने जीवनकाल में कोई विभाजन नहीं किया  
लीगल वारिस जमाबंदी में आ चुके हैं। जमाबंदी के अनुसार सभी वारिस अपने  
सक्षम न्यायालय में चारजाई की जानी चाहिये। नामान्तरण सं0 351 के जरिये  
नामान्तरण दर्ज होना चाहिये। यदि सनद गलत है तो उसे निरस्त कराने के लिए  
मसि आवंटन हुई थी। सनद आज भी स्टूड कर रही है। वारिसों के नाम आगे  
रेखादेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि चार व्यक्तियों को  
जाकर अधीनस्थ निरस्त करमाया जावे।

ही अधील पेश कर दी गई थी। इस प्रकार निवेदन किया है कि अधील स्वीकार की  
खातेदार रेकार्ड में दर्ज है तो सुना जाना आवश्यक है। आदेश की जानकारी होले  
2005(एस0सी0)पृज 3799 का न्यायिक दृष्टान्त पेश कर निवेदन किया है कि  
आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अपने पक्ष के समर्थन में ए आई आर  
नामान्तरण कर दिया है जो प्रथमदृष्टया गलत है। मूलक व्यक्ति के खिलाफ कोई  
- इसकी तस्दीक डी आर ओ से नहीं ली गई है। मरे हुए व्यक्तियों के पक्ष में  
जारी हुई है, इसका तीस वर्ष बाद नामान्तरण किया गया है, जो सही है या नहीं  
अधीनस्थ व रेस्था सं0 1 व 2 का बराबर-2 हिस्सा है। सनद जो 1987 में  
अधीनस्थ के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि जमाबंदी में  
गई।

अधीनस्थ आदेश से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभय सुनी  
निरस्त करमाया जावे।

है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अधील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ डेटाकाल  
वर्ष के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं की जा सकती  
सनद दिनांक 19-2-87 के आधार पर अब कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। 12  
2590 दिनांक 19-2-87 का हवाला देकर अधीनस्थ डेटाकाल दर्ज किया है।  
नाम विगोपित करने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने सनद सं0  
न तो रिपोर्ट मंगाई और न ही जांच की गई। अधीनस्थ न्यायालय को जमाबंदी में  
आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ डेटाकाल पारित करने से मौके की  
बराबर लगावा दी थी। मौके पर अधीनस्थ अपने हिस्से की मसि पर काबिज बने



श्री. जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्री. जिला मजिस्ट्रेट (प.प.)

श्री. जिला मजिस्ट्रेट के पी.पी. सिविल  
1-1-16 की वजह से 31-12-15 को जारी  
उत्प्रेषण आदेश का प्रतिलिपि

श्री. जिला मजिस्ट्रेट (प.प.)  
श्री. जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
(कॉर्पोरेट गवर्नर)  
11/12/16

रजि० सं. सनद की प्रमाणित प्रति संलग्न है, जिसके अनुसार सनद सं० 2590  
दिनांक 19-2-87 को जारी हुई है। सनद में दयालसिंह, भगवानकौर, करतारसिंह  
एवं गोपालसिंह कुल चार सदस्यों के नाम अंकित हैं। सनद के आधार पर ही  
अपीलाधीन इंतकाल दयालसिंह, भगवानकौर, करतारसिंह एवं गोपालसिंह के नाम  
दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। यदि अपीलान्त को सनद पर कोई आपत्ति है तो  
उन्हें सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर अनुरोध प्राप्त करना चाहिये। अपीलाध्यक्ष  
न्यायालय द्वारा सनद के आधार पर इंतकाल स्वीकृत करने में कोई कानूनी भूल  
सिद्धी की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्तस अस्वीकार किये जाने योग्य  
फलस्वरूप, अपील अपीलान्तस खारिज की जाती है तथा अपीलाध्यक्ष  
न्यायालय के अपीलाधीन इंतकाल की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति के साथ  
रेकॉर्ड अपीलाध्यक्ष न्यायालय को भेजा जावे।  
आदेश आज दिनांक 31-12-15 को भेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले  
न्यायालय में सुनाया गया।



5/17